अनंगपुर डेरी में अवैध निर्माण के पीछे एमसीएफ के अफसर खुल्लमखुल्ला शामिल

डीसी ने निगम कमिश्नर से रिपोर्ट भी मांगी लेकिन उन्हें कोई जवाब तक नहीं दिया गया

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) और नगर योजनाकार (एसटीपी) मिलकर फरीदाबाद में रसूखदारों की अवैध बिल्डिंगें बनवाने और गरीबों की झुग्गी-झोंपड़ियां उजाड़ने के घिनौने खेल में शामिल हैं। शहर के तमाम इलाकों में अवैध रूप से निर्माण कार्य हो रहे हैं, चूंकि उनका संबंध रसूखदारों या सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों से है तो उस तरफ न तो एमसीएफ, न एसटीपी और न ही हूडा देखता है। लेकिन तमाम इलाकों में झुग्गी - झोपड़ियों को यह कहकर उजाड़ा जा रहा है कि ये खेती वाली जमीन पर बनी हैं। लेकिन जब सस्ती जमीन खरीदकर गरीब लोग इन पर मकान बना रहे थे, तब एमसीएफ, एसटीपी और हूडा वहां उन्हें चेतावनी देने नहीं पहुंचा। अनंगपुर डेरी में इस समय चल रहा अवैध निर्माण एमसीएफ के अफसरों की मिलीभगत की कहानी साफ बता रहा है। एमसीएफ के कमिश्नर को अपनी कुर्सी का इतना घमंड है कि उन्होंने इस संबंध में डीसी फरीदाबाद द्वारा लिखे गए सरकारी पत्र का न तो जवाब दिया और न ही डीसी के पत्र पर कोई कार्रवाई की।

क्या है मामला

दिल्ली-फरीदाबाद बॉर्डर के पास स्थित अनंगपुर डेरी में खसरा नंबर 1667/3 की जमीन पर खुलेआम अवैध निर्माण किया जा रहा है। यह जमीन लाल डोरा से बाहर है। इस जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर जुलाई महीने से ही सीएम विंडो, एमसीएफ और जिला उपायुक्त से एक जागरूक नागरिक सुशील यादव की ओर से लगातार शिकायत की जा रही है। तमाम दस्तावेजों की जांच पड़ताल से पता चलता है कि सुशील यादव ने सबसे पहले नगर निगम के एक्सईएन (एनफोर्समेंट) विजय ढाका से इस मामले की शिकायत की। यही शिकायत एमसीएफ के ओल्ड जोन के एसडीओ एनफोर्समेंट डी.के. सोलंकी से की गई। इसके बाद नगर निगम ने अपने पटवारी को मौके पर जांच के लिए भेजा। पटवारी ने मौका मुआयना करने के बाद 29 जुलाई को रिपोर्ट दी, जिसमें स्वीकार किया गया कि मौके पर निर्माण तो हो रहा है और वह जमीन लाल डोरा से बाहर है यानी अनअप्रूव्ड है।

सूत्रों ने बताया कि पटवारी की रिपोर्ट आने के बाद एसडीओ डी.के. सोलंकी और जेई सुरेंद्र हुड्डा मौके पर पहुंचे। इन लोगों ने भी अवैध निर्माण कर रहे लोगों को नोटिस दिया। इसके बाद अवैध निर्माण रुक गया। लेकिन करीब डेढ़ महीने की चुप्पी के बाद वहां फिर से अवैध निर्माण शुरू हो गया। आरोप है कि कुछ एमसीएफ अफसरों से सांठगांठ होने के बाद उस जगह पर अवैध निर्माण दोबारा शुरू हुआ है। हालांकि इस मामले में डीसी फरीदाबाद ने भी 7 सितम्बर 2020 को एक पत्र भेजकर एमसीएफ के कमिश्नर से इस अवैध निर्माण के बारे में सूचना मांगी लेकिन कमिश्नर आफिस उस पत्र को दबाकर बैठ गया और अब हालात ये हैं कि एमसीएफ के कुछ अफसरों के सहयोग से वहां धड़ल्ले से काम चल रहा है।

एमसीएफ की मिलीभगत से अनंगपुर डेरी में खुलकर हो रहा है अवैध निर्माण

दरअसल, इस जमीन की टाइटिल किसी रमेश चंद गुप्ता के नाम से है, जिस पर उनके पुत्रों का मालिकाना हक है। जमीन पर अवैध निर्माण इस ढंग से किया जा रहा है कि वह शॉपिंग कॉम्पलैक्स नजर आती है। इसमें दुकानों का भी प्रावधान किया गया है। बन रही बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में परिवार के ही कुछ लोगों को लाकर रखा गया है ताकि ये लगे कि यह रिहायशी बिल्डिंग है जबकि मौके पर यह शॉपिंग कॉम्पलैक्स की तरह बनाई जा रही है। इस बन रही बिल्डिंग के पास इलाके का कम्युनिटी सेंटर है। असली खतरा इस कम्युनिटी सेंटर को है। कम्यूनिटी सेंटर और इस बिल्डिंग के बीच में एक सड़क है। शॉपिंग कॉम्पलैक्स शुरू होने पर इस सड़क पर वाहनों का कब्जा होना तय है। ऐसे में कम्युनिटी सेंटर में जब कार्यक्रम होंगे तो उसमें आने वाले लोग अपने वाहन कहां खड़ा करेंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

राजनीतिक संरक्षण

शहर में इस समय अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है। ज्यादातर में एमसीएफ या हूडा का सीधा हस्तक्षेप है लेकिन इन्हीं दोनों एजेंसियों के कुछ अफसर राजनीतिक संरक्षण में इन अवैध निर्माणों को करवा रहे हैं। एमसीएफ और हूडा के एसडीओ, जेई, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी सीधे भाजपा विधायकों, मंत्रियों के आदेश पर काम कर रहे हैं। आम तौर पर किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए दोहरा राजनीतिक संरक्षण मिलता है। अवैध निर्माण करने वाला भी उसी भाजपा नेता के पास पहुंचता है जिनके पास पहले से ही ऐसे अफसरों और कर्मचारियों का नेक्सस मौजूद है। अनंगपुर डेरी में हो रहा अवैध निर्माण भी इससे अछूता नहीं है। बताया जाता है कि एक भाजपा पार्षद का हाथ अवैध निर्माण करने वालों पर है। एनआईटी 5 में पिछले दिनों एमसीएफ ने एक बिल्डिंग पर सील लगाई लेकिन कुछ दिनो बाद उस बिल्डिंग से नगर निगम की सील गायब हो गई और अवैध निर्माण फिर से शुरू हो गया। एनआईटी 5 में एमसीएफ के कुछ अफसर तो संगठित रूप से इस अपराध में शामिल हैं।

एमसीएफ, हूडा और एसटीपी ने हाल ही में सेहतपुर, सरूरपुर, फरीदाबाद बाईपास, खोरी आदि इलाकों में जमकर अवैध रूप से बसी झुग्गी बस्तियों और मकानों को तोड़ा। इन पर आमतौर पर गरीब तबके के लोगों ने भूमाफिया से सस्ती जमीन लेकर रहने के लिए एक-दो कमरे बना रखे थे।

इनमें कुछ निर्माण खेती वाली जमीनों पर भी हैं। लेकिन भूमाफिया जब यहां प्लॉट काट रहा था और अवैध रूप से निर्माण हो रहा था तो एमसीएफ, हूडा और एसटीपी के अधिकारी-कर्मचारी गायब थे, क्योंकि तब यहां से उन लोगों को रिश्वत पहुंच रही थी। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार ने झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने की योजना बनाई और इन एजेंसियों को आदेश दिया तो रिश्वत में मिली रकम भूलकर अफसरों-कर्मचारियों ने गरीबों के आशियाने पर जेसीबी चला दी।

माफिया ने कहा - डीसी के आदेश पर चला रहे हैं पार्किंग

सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर पार्किंग माफिया सड़क पर गाड़ी खड़ी करवाकर रास्ता बंद कर देता है

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः सेक्टर 12 में लघु सचिवालय के पास मल्टीलेवल पर्किंग की घोषणा होने के बावजूद पिछले दो साल से एक इंच भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। सेक्टर में पार्किंग के लिए नाप, पैमाना सब लिया जा चुका है, लेकिन मैंटेनेन्स का प्रारूप तय न हो पाने के कारण आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया।

प्रशासनिक दृष्टि से सेक्टर 12 फरीदाबाद का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ डीसी दफ्तर के साथ-साथ जिला न्यायालय, फरीदाबाद तहसील और हुडा दफ्तर भी है। इतना ही नहीं, टैक्स विभाग का दफ्तर, टाउन पार्क और सेन्ट्रल थाना की बिल्डिंग भी कोर्ट के सामने स्थित है। रेडक्रॉस सोसाइटी के दफ्तर के अलावा खेल परिसर है। लघु सचिवालय के सामने आये दिन धरना प्रदर्शन भी होते रहते हैं।

पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने से प्रशासनिक बिल्डिंग के इस इलाके में पार्किंग के नाम पर सड़क पर ही लोग गाड़ियाँ पार्क करते है। यूँ तो यह कोई ऐसी बात नहीं जो केवल फरीदाबाद में ही हो रही है। परन्तु बड़ी बात है यहाँ होने वाली अवैध वसूली और वो भी जिले के लगभग कार्यपालिका और न्यायपालिका की ठीक नाक के नीचे।

सड़क पर पार्किंग, सेन्ट्रल थाना क्षेत्र से लेकर टाउन पार्क को कवर करती हुई डीसी बिल्डिंग के दोनों तरफ की सड़क पर चार लेन में पार्किंग लगाई जाती है। इतना ही नहीं कोर्ट के ठीक सामने बनने वाला तिराहा जो खेल परिसर और आयकर बिल्डिंग की तरफ जाता है उस पर पार्किंग माफिया इस तरह गाड़ियाँ पार्क करवाता है कि दो तरफ का रास्ता पूरी तरह से ही बंद हो जाता है। शर्म की बात है कि अदालत जाने वाले जज भी ठीक इसी गेट से घुसते हैं और वही रास्ता बंद है।

गाड़ियों की पार्किंग के पैसे लेने वाले एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि एक ही सड़क पर दोनों तरफ आप कैसे गाड़ी पार्क करवा रहे हैं, इसकी इजाजत आपको किसने दी तो उसने सुनील नामक व्यक्ति का नाम लेकर बताया कि उसका ठेका है। दोनों तरफ से और तिराहे व मोड़ों पर रास्ता बंद करने के सवाल पर जीतू नामक पार्किंग अटेंडेंट ने धमकाते हुए कहा, आपको कोई तकलीफ हुई हो तो कहो और अगर शिकायत करनी है तो कर लो, डीसी साहब के आदेश से कर रहे हैं।

पार्किंग माफिया के इस अतिक्रमण को न रोक पाने वाले अफसरों की हरकत की वजह से पार्किंग के नाम पर पैसे की अवैध वसूली हो रही है। आम लोगों के आने-जाने के रास्ते को अवैध रूप से पूरी तरह बंद कर उस पर कब्जा किया जा रहा है।

खबर मरम्मत

जुम्मन मियां पंक्चर वाले

बाईडन से तू तू-मैं मैं के बीच ट्रम्प को कोरोना

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिये तीन नवम्बर को चुनाव होने हैं। वहां की बहुत ही खूबसूरत परम्परा के मुताबिक दोनों प्रमुख पार्टियों, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार टीवी पर आमने-सामने एक बहस में हिस्सा लेते हैं। पूर्व में यह बहस बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुई हैं क्योंकि इससे विभिन्न नीतिगत मामलों में दोनों उम्मीदवार अपने विचार प्रकट करते हैं और उनके इन विचारों के आधार पर मतदाता अपने समर्थन का निर्णय करते हैं। यह बहस बहुत ही शालीन और सारगर्भित होती रही है। लेकिन इस बार की बहस ने अमेरिका को पूरे विश्व में शर्मसार कर दिया। ट्रम्प ने अनेकों बार अपने प्रतिद्वंदी को बीच में टोका और अनावश्यक टिप्पणियां की। ट्रम्प प्रमुख मुद्दों पर बोलने के बजाय बाईडन पर व्यक्तिगत आक्षेप करते रहे। जवाब में बाइडन ने भी उन्हें 'शट-अप' और जोकर कहा। इस बीच ट्रम्प और उनकी पत्नी को कोरोना हो गया है।

पूरे विश्व में पूंजीवाद पर छाये संकट के बादल

इन सभी देशों में सरकारों को अपने बचाव में कहने को कुछ नहीं मिल रहा। भारत में तो मोदी ने धार्मिक घृणा का ऐसा अमोघ मंत्र फूंक रखा है कि यहां पर तो नीतिगत किसी मामले पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। और उठा भी दे तो मोदी जी कौन सा जवाब देने बैठे हैं, वहां तो सिर्फ़ वन वे ट्रैफिक (एकतरफ़ा भाषणबाज़ी) है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। हालांकि ट्रम्प की पूरी कोशिश है कि बहस नीतियों की बजाय रेस की महानता, गोरों की प्रभुता, की तरफ़ मुड़ जाये पर ऐसा अभी संभव होता नहीं दिख रहा। ट्रम्प ने अपने अन्धभक्तों के ग्रुप 'प्राऊड ब्वायज', जो गोरों की प्रभुता की बात करते हैं, कि निन्दा करने से भी मना कर दिया। अमेरिका का ये चुनाव खुद अमेरिका और विश्व के लिये एक क्रान्ति सिद्ध हो सकता है और इसमें खून खराबे से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। तीन नवम्बर का इंतजार कीजिये क्योंकि मोदी के आका के भविष्य से भारत का भी भविष्य जुड़ा है।

राज्यपाल या पुलिस प्रमुख ?

जब भी किसी के साथ कोई अपराध घटित होता है तो वह एफ़आईआर लिखाने थाने में जाता है, एसएचओ से मिलता है। वहां से संतुष्ट नहीं हो तो एसपी, डीआईजी या आईजी से मिलता है। और अन्त में पुलिस प्रमुख के सामने अपनी शिकायत रखता है। लेकिन महाराष्ट्र में जिसको भी शिकायत होती है वो थाने जाये या न जाये सीधा राज्यपाल से जरूर मिलता है। पहले कंगना रनौत जाकर राज्यपाल से मिली कि मेरा बंगलें का अवैध हिस्सा महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी से तुड़वा दिया। अब अभिनेत्री पायल घोष भी केन्द्रीय मंत्री अठावले को लेकर राज्यपाल से मिली हैं। उनकी शिकायत है कि उन्होंने जब फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर बलात्कार करने (कई साल पहले) का आरोप लगा दिया तो उन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा।

समझ नहीं आता कि यूपी में एक से एक क्रूर बलात्कार हो रहे हैं, पीड़िताओं की जघन्य हत्यायें हो रही हैं, वहां कोई जा के राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं कहता उन्हें कि मेम साहेब बलात्कार के 15 दिन बाद एक एफ़आईआर भी दर्ज नहीं कर रही पुलिस? क्यों नहीं बीजेपी का कोई नेता वहां बलात्कार पीड़िता को साथ लेकर राज्यपाल से मिलता कि गवर्नर साहिबा ये मुख्यमंत्री अपराधियों से मिला हुआ है इसे बाहर का रास्ता दिखाओ, हटाओ इसे। या फ़िर ये शक्तियां सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों के गवर्नरों के पास ही हैं!

किसानों की फुर्ती ने मोदी के झूठ की खोली पोल

मोदी जी ने संसद में आपाधापी के बीच तीन कृषि सम्बंधी कानून पास करवा लिये। राज्यसभा में तो बहुमत भी नहीं था तो वोटिंग भी नहीं करवाई-ध्वनिमत से बिना बहस के ही बिल पास घोषित कर दिये गये। राष्ट्रपति तो बैठे ही रहते हैं पलक पावंड़े बिछाये कि वो मोदी जी के किसी काम आ सकें, सो उनहोंने भी तुरन्त जाते ही इन बिलों पर मुहर लगा दी और ये कानून बन गये। मोदी जी ने इन नये कानूनों का महत्व समझाते हुये कहा कि अब कोई भी किसान अपनी फ़सल पूरे भारत में कहीं भी बेच सकेगा और उसे उसका एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा।

मोदी जी के इन वचनों की गूंज थमी भी न थी कि यूपी के किसानों ने भी फुर्ती दिखायी और वे भी तुरन्त 50 ट्राली गैर बासमती चावल की भर कर हरियाणा के करनाल में बेचने चल दिये। क्योंकि यूपी में गैर बासमती चावल पर एमएसपी नहीं मिलता लेकिन हरियाणा में मिलता है सो वह अपना चावल हरियाणा में बेचना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोदी जी के खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। उनकी फुर्ती किसी काम नहीं आयी और हरियाणा पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक कर वापिस भेज दिया। लौट के बुद्धू घर को आये। लेकिन मोदी जी के गपोड़ों का खुलासा जरूर कर आये ।

अन्तिम मिसरा

हत्या हो या सीता का होता रहे बलात्कार,
हम तो करेंगे बस मंदिर निर्माण।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06